उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 2, अंक : 12 ₹ 20/- 16-30 नवम्बर, 2018

कश्मीर में फैल रहा है जिहादी

इस्लामी संगठनों का मकड़जाल

आई.एस.आई.एस. में शामिल आतंकवादी एहतेशाम बिलाल

और पढ़ें...

- राम मंदिर बनाने का समर्थन
- सउदी अरब के युवराज को हटाने का अभियान
- मुस्लिम महिलाएं अमेरिकी कांग्रेस के लिए निर्वाचित
- अबू आसिम आजमी के खिलाफ मुकदमा

RNI No. DELHIN/2017/72722

Vol. 2, अंक 12

16-30 नवम्बर, 2018

परामर्शदाता
प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह, आशीष रावत

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाईट : www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक एवं प्रकाशक मनमोहन शर्मा द्वारा
भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए
डी-51, प्रथम तल, हौज खास,
नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित
तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा. लि., ए 102/4,
ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II,
नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. कश्मीर में फैल रहा है जिहादी इस्लामी संगठनों का मकड़जाल

II. टीपू सुल्तान का जन्मदिवस मनाने पर बवाल

III. राम मंदिर बनाने का समर्थन

IV. विवादों के घेरे में ताजमहल की मस्जिद

V. स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे का महिमामंडन

पश्चिमी एशिया

I. सउदी अरब के युवराज को हटाने का अभियान

II. गाजा में जंग बंदी

III. सउदी अरब में हजारों इंजीनियरों की छुट्टी

IV. अरबों दीनार का घोटाला

V. ईरान में सरकार के खिलाफ महागठबंधन

VI. जॉर्डन का इजरायल से शांति समझौता समाप्त

विश्व

I. मुस्लिम महिलाएं अमेरिकी कांग्रेस के लिए निर्वाचित

II. बांग्लादेश चुनाव में भाग लेंगे विपक्षी दल

III. बलात्कार के आरोप में मुस्लिम विद्वान गिरफ्तार

IV. पाकिस्तान में पूर्व पुलिस अधिकारी की हत्या

V. सात लाख अफगानियों की वापसी

VI. ऑस्ट्रेलिया को इस्लाम से खतरा

VII. तब्लीगी जमात के प्रमुख का निधन

VIII. ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कार्यक्रम में धमाका

अन्य

I. अबू आसिम आजमी के खिलाफ मुकदमा

II. वीडियो कॉल पर निकाह

III. इमामों के वेतन वृद्धि की मांग

IV. जिहादियों का शिकार पुलिस अधिकारी

V. आसिया अंद्राबी के खिलाफ मुकदमा

VI. जर्मनी में जिहादी संगठन पर छापे

सारांश

जिहादी संगठनों में शामिल होने का जुनून कश्मीरी युवकों में तेजी से फैल रहा है। चिन्ताजनक बात यह है कि जिन छात्रों ने कलम छोड़कर बन्दूक उठाई है उनमें से अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। कश्मीर घाटी में अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी इस्लामी संगठनों का मकड़जाल बड़ी तेजी से फैल रहा है। देश के अधिकांश राज्यों में उग्रवादी संगठन अपनी जड़ें जमा चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि इनके उन्मूलन के लिए सरकार सख्त कदम उठाए।

टीपू सुल्तान का जन्मदिवस मनाने पर कर्नाटक में एक बार फिर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने टीपू सुल्तान के जन्मदिवस को सरकारी तौर पर मनाने का जो फैसला किया था उसे वर्तमान राज्य सरकार ने भी जारी रखा है। टीपू सुल्तान एक विवादित शासक था। कई इतिहासकारों का मत है कि टीपू सुल्तान ने इस्लाम को तलवार के जोर से केरल और कुर्द में फैलाया व अनेक गैर-मुसलमानों की हत्याएं कीं। यही कारण है कि हिन्दू संगठनों द्वारा टीपू सुल्तान के जन्मदिवस को सरकारी तौर पर मनाने का विरोध किया जाता है।

ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के मुद्दे ने एक बार फिर नया रूप ले लिया है। पुरातत्व विभाग ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद इस प्रतिबंध की धज्जियां उड़ाई गई और वहां पर नमाज पढ़ी गई। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो कुछ महिलाएं वहां पूजा-पाठ करने के लिए पहुंच गईं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पूजा-पाठ के बारे में जो दावा किया गया है वह सही नहीं है।

देश की राजधानी दिल्ली में अतिवादी संगठन फिर से सिर उठाने लगे हैं। हाल में ही एक धार्मिक परिसर में एक समारोह का आयोजन करके स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे अब्दुल रशीद को महिमामंडित करने का प्रयास किया गया। ज्ञातव्य है कि गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक और विख्यात् आर्य समाजी सन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द की निर्मम हत्या सन् 1926 में अब्दुल रशीद नाम के एक व्यक्ति ने कर दी थी। जिसके बाद न्यायालय ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी। इतने वर्षों बाद उसे महिमामंडित करने का जो अभियान शुरू किया गया है इसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। इस समारोह की अध्यक्षता एक विवादित इमाम ने की।

सउदी अरब के युवराज विवादों के घेरे में हैं। उन पर एक विरोधी पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या करवाने का आरोप है। पहले इस मुद्दे को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खूब उछाला था क्योंकि यह पत्रकार अमेरिकी समाचारपत्र वाशिंगटन पोस्ट में काम करता था। समाचारपत्रों में यह समाचार भी प्रकाशित हुए कि सीआईए ने इस हत्या में सउदी अरब के युवराज का हाथ बताया है। हालांकि न जाने किस दबाव के कारण डोनाल्ड ट्रम्प ने इस आरोप का खंडन कर दिया। इस घटना के कारण सउदी अरब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शाही परिवार का एक वर्ग मांग कर रहा है कि युवराज मोहम्मद बिन सलमान को उनके पद से हटाकर शाह सलमान के भाई अब्दुल अजीज को युवराज नियुक्त किया जाए। ज्ञातव्य है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सउदी अरब में अपने विरोधियों के खिलाफ दो वर्ष पूर्व जोरदार अभियान चलाया था और शाही वंश के अनेक शहज़ादों को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर जेल में बंद कर दिया था।

राष्ट्रीय

I

कश्मीर में फैल रहा है जिहादी इस्लामी संगठनों का मकड़जाल

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (4 नवम्बर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के शारदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक कश्मीरी छात्र एहतेशाम बिलाल एक जिहादी संगठन में शामिल हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक ऑडियो और तस्वीर के अनुसार एहतेशाम बिलाल ने इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू-कश्मीर नामक उग्रवादी संगठन में शामिल हुआ है। वायरल हुई तस्वीर में उसे इस्लामिक स्टेट के झंडे के पास खड़े हुए दिखाया गया है जिसमें वह इस्लामिक स्टेट के जम्मू-कश्मीर यूनिट की स्थापना करते हुए दिखाई दे रहा है। एहतेशाम बिलाल श्रीनगर के खानयार मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस इस संदर्भ में जांच कर रही है। बिलाल के परिजनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह बिलाल का पता लगाए। उन्होंने कहा कि बिलाल हमारा इकलौता बच्चा है।

चौथी दुनिया (19 नवम्बर) ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। हारून रेशी नामक व्यक्ति के अनुसार एहतेशाम बिलाल 28 अक्टूबर की सुबह विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारियों को यह कहकर निकला था कि वह दिल्ली जा रहा है। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि बिलाल सीधा हवाई अड्डे गया और वहां से श्रीनगर जाकर दक्षिण कश्मीर में उग्रवादी संगठन में चला गया। 20 वर्षीय एहतेशाम बिलाल शारदा विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र है। 14 अक्टूबर को कश्मीरी छात्रों और स्थानीय छात्रों के बीच मारपीट हुई थी जिसमें बिलाल भी जख्मी हुआ था। कश्मीर पुलिस ने बिलाल के आतंकी संगठन में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। बिलाल के परिजन उसके आतंकी संगठन में शामिल होने से परेशान हैं।

समाचारपत्र ने कहा कि आतंकवादी संगठन अंसार गंजवात-उल-हिन्द में एहतेशाम बिलाल के शामिल होने की चर्चा है। दो वर्ष पूर्व कश्मीर घाटी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएसआईएस नहीं था। 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की लहर के दौरान पहली बार श्रीनगर की ऐतिहासिक मस्जिद के बाहर कुछ नौजवान आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए दिखाए दिए। इस वर्ष के मार्च माह में दक्षिण कश्मीर के अनन्तनाग जिले में पहली बार सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में आईएसआईएस के तीन आतंकवादी मारे गए थे जिनमें दो कश्मीरी थे जबकि तीसरा तेलंगाना का रहने वाला था। इस वर्ष 3 जनवरी को पहली बार केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस संगठन के मौजूद होने की पुष्टि की थी। घाटी में तैनात सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए. के. भान ने कूपवाड़ा में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दावा किया था कि घाटी में तीन सौ से अधिक सशस्त्र उग्रवादी सक्रिय हैं। पुलिस के अनुसार दक्षिण कश्मीर में 181 आतंकी सक्रिय हैं और चारों जिलों अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां हिंसा की चपेट में हैं। अनंतनाग में 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था वह आज भी जारी है। सेना एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियां गत 30 वर्ष से निरंतर जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद को समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं लेकिन सच्चाई है कि 30 वर्ष में सुरक्षाबलों का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है।

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में दावा किया है कि एहतेशाम बिलाल आईएसआईएस का सदस्य बन गया है तो ये चिन्ता की बात है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घाटी में आतंकवादियों को भर्ती कर रहे हैं और पढ़े-लिखे नौजवान इस विचारधारा से प्रेरित हो रहे हैं। सरकारी सूत्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि गत दो वर्ष में जो युवा वर्ग आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसमें से काफी युवक उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड़ में चार उच्च शिक्षा प्राप्त आतंकी मारे जा चुके हैं इनमें अजहरुद्दीन, डॉ. मोहम्मद रफीक बट, मन्नान वानी और सब्ज़ार बशीर शामिल थे। अजहरुद्दीन ने अरबी में पीएचडी की हुई थी जबकि रफीक कश्मीर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। मन्नान वानी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है जबकि सब्ज़ार ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। मगर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठन कश्मीर में अपने पैर फैला रहे हैं और नए युवकों को आतंकी संगठन में भर्ती कर रहे हैं वह वास्तव में चिन्ताजनक की बात है।

टिप्पणी: हाल में ही देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले कश्मीरी छात्रों के संबंध आतंकी संगठनों से पाए गए हैं। जालंधर में ऐसे कश्मीरी छात्रों का एक गिरोह पकड़ा गया जिनके संबंध इन आतंकवादी संगठनों से हैं। उनके कब्जे से एके-47 और अन्य अस्त्र-शस्त्र बरामद हुए हैं। साफ है कि जो कश्मीरी छात्र जम्मू-कश्मीर के बाहर विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके तार जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जो कश्मीरी छात्र जम्मू-कश्मीर के बाहर के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके आवास, भोजन, शिक्षा और पुस्तकों का पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है। केन्द्र सरकार की एक विशेष योजना के अनुसार प्रतिवर्ष कश्मीर घाटी से पांच हजार छात्र रियासत के बाहर के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं। इनमें से तीन हजार छात्र प्रोफेशनल और टेक्निकल विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं जबकि सौ से अधिक छात्र डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करते हैं। शेष छात्रों को स्नातकोत्तर के लिए प्रतिवर्ष दो लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। खास बात है कि इन छात्रों के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालयों में विशेष स्थान सुरक्षित हैं जिसके कारण इन्हें इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में कोई परेशानी नहीं होती।

II

टीपू सुल्तान का जन्मदिवस मनाने पर बवाल

इंकलाब (11 नवम्बर) ने इस समाचार को प्रमुख रूप से प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है 'बीजेपी का विरोध विफल, टीपू का जन्मदिन मनाया गया'। समाचारपत्र के अनुसार कर्नाटक सरकार ने टीपू सुल्तान का जन्मदिवस सरकारी तौर पर मनाया लेकिन भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों ने इसका विरोध किया। भाजपा ने धमकी दी थी कि वह इस आयोजन को नहीं होने देगी। इसके बाद हुबली, धारवाड़, शिमोगा आदि कई नगरों में राज्य सरकार ने धारा-144 लगा दी थी। भाजपा ने मांग की थी कि टीपू सुल्तान का जन्मदिवस न मनाया जाए क्योंकि वह एक जालिम शासक था। इस मांग को मनवाने के लिए भाजपा ने राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन किए। भाजपा के अनुसार टीपू एक कट्टर मुसलमान था और उसने अनेक मंदिर तोड़े थे एवं

व्यापक स्तर पर हिन्दुओं का धर्मांतरण किया था। भाजपा नेता शोभा कारनदलाजे ने कहा कि टीपू का जन्मदिवस मनाने के ही कारण कांग्रेस के सिद्धारमैया को गद्दी से हाथ धोना पड़ा था और अब कुमारस्वामी को भी यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस और जनता दल (एस) के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने घोषणा की थी कि वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए सरकारी तौर पर टीपू सुल्तान का जन्मदिवस मनाएगी। एक जिला में भाजपा के तीन विधायकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जो कि टीपू का जन्मदिवस मनाने का विरोध कर रहे थे। कई अन्य जगहों पर भी टीपू की जयंती मनाने का विरोध करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जबकि मैसूर, मांड्या आदि कुछ जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया।

अखबार मशरिक (11 नवम्बर) के अनुसार कर्नाटक में टीपू सुल्तान का जन्मदिवस मनाने पर विवाद उत्पन्न हो गया है। समाचारपत्र के अनुसार पुलिस ने भाजपा के तीन विधायकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारी कांग्रेस और जनता दल (एस) सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे।

सियासत (11 नवम्बर) के अनुसार कर्नाटक में भाजपा और दक्षिणपंथी विरोध के बावजूद टीपू जयंती मनाई गई। इस जयंती में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और उप-मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर शामिल नहीं थे। ये दोनों विधान सौध में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले थे मगर वे नहीं आए। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने का निर्देश दिया है इसलिए उन्होंने इस समारोह में भाग नहीं लिया। जबकि उप-मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर बेंगलुरु से बाहर थे इसलिए वे इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके। समाचारपत्र ने आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान की जयंती का आयोजन करने के प्रश्न पर सत्तारूढ़ गठबंधन में भारी मतभेद थे। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं के दबाव के कारण इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया।

दावत (16 नवम्बर) ने एक सम्पादकीय में कहा कि भाजपा ने इस समारोह का विरोध किया था मगर इसके बावजूद राज्य सरकार ने इस समरोह को रद्द नहीं किया। हालांकि कई क्षेत्रों में धारा-144 लगाई गई और कई क्षेत्रों में गिरफ्तारी भी की गई। मगर टीपू सुल्तान की जयंती शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। टीपू का जन्म 10 नवम्बर 1750 में हुआ था। राज्य के क्षेत्रों में तभी से टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की परम्परा चली आ रही है। जब 2015 में कांग्रेस सरकार ने सरकारी तौर पर इस जन्मदिवस को मनाने का फैसला किया तो विवाद उत्पन्न हुआ। भाजपा ने इसे साम्प्रदायिक रंग देने के साथ-साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ एक अभियान चलाया और उन्हें हिन्दू व हिन्दू धर्म का विरोधी बताया। जिसके कारण जनमानस में उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। जब भाजपा को मुसलमान शासकों के नामों पर शहरों और सड़कों के नामों पर आपत्ति है तो वे टीपू सुल्तान को कैसे सहन कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना सही है कि अंग्रेजों के नाम पर बने किसी भी संस्थान का नाम आज तक नहीं बदला गया। सिर्फ मुस्लिम नाम ही बदले गए हैं। कभी भाजपा नेता टीपू सुल्तान के मजार पर जाते थे मगर अब वह उनकी जयंती के विरोध का ड्रामा कर रहे हैं। समाचारपत्र के अनुसार जनता दल (एस) और कांग्रेस की गठजोड़ की सरकार के समय में पहला अवसर है जब टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जा रही है। भाजपा और मीडिया ने भ्रांति फैलाने का प्रयास किया था कि कांग्रेस के दबाव पर जयंती मनाई जा रही है। भाजपा की ओर से टीपू सुल्तान का चरित्र हनन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने कई स्थानों पर मंदिर तोड़े थे और काफी हिन्दुओं का कत्ल किया था व जबरन धर्मांतरण करवाया था लेकिन इसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। इतिहासकार भी इन आरोपों का खंडन करते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में जो मनगढ़ंत बात की जा रही है वह गलत हैं।

टिप्पणी: टीपू सुल्तान एक विवादित शासक था। कुछ लोग उसे धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता सेनानी घोषित करते हैं। जबकि दूसरे वर्ग का कहना है कि टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखा है कि उसका मुख्य कार्य काफिरों का सफाया करना है। इतिहासकारों के अनुसार 1760 में नरका चतुर्दशी के दिन सुल्तान के सैनिकों ने मेलकोटे नामक कस्बा में 800 अयंगर ब्राह्मणों की हत्या कर दी। इनमें कई बच्चे व महिलाएं भी थीं। घटना के बाद इस कस्बा में कभी दीवाली नहीं मनाई जाती। दो अंग्रेज लेखकों जस्टिन एम. कोर्डवैल और रोनाल्ड ए. स्क्वार्ज़ के अनुसार जो लिंगायत महिलाएं ऊपर से शरीर को नग्न रखती थीं उनके खिलाफ भी टीपू सुल्तान के आदेश से कार्रवाई की गई। मैंगलुरु बंदरगाह में टीपू सुल्तान ने कोडवा सम्प्रदाय पर हमला किया और अनेक कोडवा मारे गए। एक अन्य इतिहासकार लेवीस राइस के अनुसार टीपू सुल्तान ने करनाल के नवाब को एक पत्र भेजा जिसमें उसे निर्देश दिया कि युद्ध में जो हिन्दू बंदी बनाए गए हैं उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जाए और जिन लोगों ने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया उनकी हत्या कर दी गई। इस बात की पुष्टि मोहीबुल हसन ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान' में की है। टीपू सुल्तान को इस संदर्भ में बेकल के गर्वनर बुदरुज़ जुमान खां ने 1790 में एक पत्र लिखकर सूचना दी। इसी तरह से मैंगलुरु में भी अनेक ईसाईयों की हत्या की गई और उनका जबरन धर्मांतरण किया गया।

III

राम मंदिर बनाने का समर्थन

इत्तेमाद (12 नवम्बर) के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद गैयूरुल हसन रिजवी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का समर्थन किया है और कहा है कि इससे देश में मुसलमान इज्जत और अमन-चैन के साथ रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए ताकि दोनों सम्प्रदायों के बीच सद्भावना बनी रही। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक आयोग को कुछ संगठनों द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि देश में मुसलमान भय के वातावरण में जी रहे हैं। इस ज्ञापन में वातावरण में सुधार करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ संगठनों ने यह भी मांग की है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के निर्माण में मुस्लिम संगठनों के सहयोग से विवाद खत्म हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग समझता है कि आयोध्या में अब मस्जिद के पुनर्निर्माण की कोई सम्भावना नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि उस जगह पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही नमाज पढ़ी जा सकती है क्योंकि इस स्थान पर एक करोड़ हिन्दुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर राम मंदिर बनाने की अनुमति दे दी जाए तो इससे देश में अमन-चैन स्थापित हो पाएगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि राम मंदिर के मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि समाज की एकता बनी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार क्या करती है यह उसका काम है मगर मैं इस विवाद को जल्द से जल्द हल करना चाहता हूं। आम मुसलमान विवाद नहीं बल्कि शांति चाहता है। हां, कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है मगर आम मुसलमान का रवैया विवाद उत्पन्न करना नहीं है बल्कि वे इस विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और कुछ संगठन व्यक्तिगत हितों के कारण इस मामले को उलझा रहे हैं।

हालांकि आम लोग इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने इस आरोप का खंडन किया कि आने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को पुनः उठा रही है जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कई लोग चाहते हैं कि इस विवाद पर न्यायालय प्रतिदिन सुनवाई करे ताकि इसका निपटारा हो सके मगर ऐसा नहीं हो रहा इसलिए लोगों को बेचैनी हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति और भावनाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि अपने राजनैतिक स्वार्थों के कारण उन्होंने अल्पसंख्यकों का शोषण किया है।

IV

विवादों के घेरे में ताजमहल की मस्जिद

सहाफत (19 नवम्बर) ने आगरा के ताजमहल की मस्जिद में पुरातत्व विभाग ने नमाज पढ़ने पर जो प्रतिबंध लगा दिया था अब उस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। कुछ हिन्दू संगठनों ने वहां पर पूजा का सिलसिला शुरू करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। मस्जिद के इमाम का कहना है कि मस्जिद में घुसकर पूजा करने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सूचना के अनुसार हिन्दू संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने जुमा के दिन मस्जिद में घुसकर पूजा की और गंगाजल भी छिड़का। इस वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने से एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। संगठन से संबंधित मीना देवी का कहना है कि जब मुसलमानों को ताजमहल की मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति है तो उन्हें पूजा करने से कैसे रोका जा सकता है? इस संगठन का कहना है कि ताजमहल इससे पूर्व एक शिव मंदिर था। दूसरी ओर, सीआईएसएफ के कर्मचारियों का कहना है कि मस्जिद में पूजा करने का समाचार गलत है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि इस पूजा के संबंध में सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद ही सुरक्षा एजेंसियों को वहां भेजा गया था। मगर वहां पर पूजा का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। सरकार सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

इंकलाब (19 नवम्बर) ने अपने सम्पादकीय में कुछ हिन्दू महिलाओं द्वारा पूजा करने की घटनाओं की निंदा की है। सम्पादकीय में कहा गया है कि कुछ दिन पूर्व ही ताजमहल की मस्जिद में पुरातत्व विभाग ने पांच वक्त की नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब बात मीडिया में आई तो सरकारी तौर पर सफाई दी गई कि मुसलमान ताजमहल में नहीं बल्कि उसके परिसर में बनी शाही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मगर कई बार इतनी भीड़ हो जाती है कि नमाजियों की कतार ताजमहल तक पहुंच जाती हैं। शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने पर जब मुसलमानों ने आपत्ति जताई तो हिन्दू भी विवाद में कूद पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा विवाद आपसी मिलीभगत से हो रहा है। प्रश्न है कि मस्जिद शाहजहां ने नमाज पढ़ने के लिए बनाई थी या फिर पर्यटकों के देखने के लिए? देश का कौन सा विभाग ऐसा है जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक सकता है? वैसे हम बताते चलें कि हिन्दुस्तान में ऐसी सैकड़ों मस्जिद हैं जिनमें सरकार ने नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रतिबंध भाजपा के शासनकाल में नहीं बल्कि सेक्युलरवादियों के शासनकाल में लगा था। यह बात भी विचारणीय है कि देश में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है कि जिसमें शरारती तत्व अपना दावा न ठोकते हों। इस सिलसिले में पुस्तकें लिखकर और प्रचार करके देश की जनता

को गुमराह किया जा रहा है। हाल में ही मैं जब चांदनी चौक गया तो वहां एक व्यक्ति ने मेरे हाथ में एक पुस्तिका थमा दी थी जिसमें लालकिला को लालकोट कहा गया था। इसी तरह से लखनऊ के एक बड़े इमामबाड़े को हिन्दू राजमहल साबित करने के बारे में एक पुस्तक बाजार में है। पुस्तक पुरुषोत्तम नागेश ओक नामक एक व्यक्ति ने लिखी है जो झूठ बोलने को अपना धर्म समझता है। इसी मनोवृत्ति के लोग ताजमहल को भी तेजोदेवी का मंदिर बता रहे हैं और इसी गिरोह में आकर ताजमहल में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। जिस तेजी से ताजमहल को साम्प्रदायिक अपना निशाना बना रहे हैं उसे देखकर लगता है कि बाबरी मस्जिद के बाद अगला निशाना ताजमहल ही होगा।

हमारा समाज (7 नवम्बर) के अनुसार पुरातत्व विभाग ने जुमा को छोड़कर अन्य दिनों के लिए ताजमहल की मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने शाही मस्जिद में उस हौज़ पर भी ताला लगा दिया है जहां से नमाजी वजूह किया करते हैं। शाही मस्जिद के इमाम सैयद सादिक अली का आरोप है कि उन्हें भी मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया गया और कहा कि ना वे मस्जिद में नमाज पढ़ाएं और ना ही खुद पढें। इमाम का दावा है कि यह निर्देश अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि को सामने रखकर दिया है। जहां तक हौज़ पर ताला लगाने की बात है, अधिकारियों का तर्क है कि यह इसलिए किया गया है कि ताकि कोई पर्यटक हौज़ में गिरकर डूब ना जाए। ताजमहल मस्जिद प्रबंधक कमेटी के प्रमुख इब्राहिम ज़ैदी का कहना है कि इमाम को यह निर्देश पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी ने दिया है। इसके बाद मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से भेंट की और उनसे मांग की है कि इस प्रतिबंध को हटाया जाए। इमाम का दावा है कि अभी तक इस मस्जिद में प्रतिदिन पांचों वक्त नमाज होती थी। जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह इस संबंध में पुरातत्व विभाग से बातचीत करेंगे। मगर पुरातत्व विभाग का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय इससे पूर्व स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि ताजमहल की मस्जिद में केवल जुमा के दिन ही नमाज हो पाएगी और उसमें केवल स्थानीय लोग शामिल होंगे। कोई बाहरी व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकेगा। दूसरी ओर, मुसलमानों का दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश इसलिए दिया था कि क्योंकि शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है इसलिए इस निर्देश का मस्जिद में पढ़ाई जाने वाली नमाज से कोई संबंध नहीं है।

सहाफत (6 नवम्बर) ने ताजमहल की मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक फैसला दे दिया है कि नमाज के लिए मस्जिद अनिवार्य नहीं है। कश्मीर में तो लोग मस्जिदों में नमाज अदा करना भूल गए हैं क्योंकि वहां शांति व्यवस्था की आड़ में मस्जिदों पर ताले लगा दिए गए हैं। अजान पर भी रोक लगा दी गई है। अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है कि ताजमहल की मस्जिद में जुमा को छोड़कर अन्य दिनों में भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती।

V

स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे का महिमामंडन

कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे को महिमामंडित करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। **हमारा समाज** (15 नवम्बर) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार इस हत्यारे को श्रद्धांजलि अर्पित

करने के लिए बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित मदरसा रशीदियार–मस्जिद भूरी भटियारी में एक आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता तंजीम इमाम–ए–मस्जिद मौलाना अमीर इल्यासी ने की। इस अवसर पर उन्होंने गाजी अब्दुल रशीद नामक हत्यारे को शहीद करार दिया और आगे कहा अब्दुल रशीद ने पैगम्बर मोहम्मद की आलोचना करने वाले स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या सही की थी। उन्होंने कहा कि गाजी अब्दुल रशीद को अल्लाह ने मोहम्मद और दीन–इस्लाम की जानकारी दी थी जिसके कारण उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या की। ज्ञातव्य है कि आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या 23 दिसम्बर, 1926 को अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली में नया बाजार स्थित उनके घर में घुसकर कर दी थी। स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और देश में शुद्धि का अभियान चलाया था। दिल्ली में उनके हत्यारे अब्दुल रशीद को महिमामंडित करने के लिए जो समारोह आयोजित किया गया था उसमें अंजुमन जमील ने भाग लेते हुए कहा कि गाजी अब्दुल रशीद ने जो कारनामा किया था वह जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक याद किया जाएगा। अन्य वक्ताओं में मौलाना यहया कासमी, चौधरी शरीफ जैसे अनेक मुस्लिम नेता शामिल थे। इस समारोह के बाद मुस्लिम नेता अब्दुल रशीद की कब्र पर गए और वहां पर फातिया ख्वानी की और फूल चढ़ाए।

पश्चिमी एशिया

I

सउदी अरब के युवराज को हटाने का अभियान

सउदी अरब के विवादित युवराज मोहम्मद बिन सलमान को पद से हटाने का अभियान तेज हो गया है। **इंकलाब** (21 नवम्बर) के अनुसार सउदी अरब के शाही परिवार के लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान को युवराज पद से हटाने का अभियान तेज कर दिया है। इनका प्रयास है कि सलमान को हटाकर वर्तमान युवराज के भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज को नया युवराज बनाया जाए। ज्ञातव्य है कि अब्दुल अजीज अपनी जान बचाने के लिए सउदी अरब से भागकर विदेश चले गए थे। अब वे अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद वापस लौटे हैं। तुर्की और अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि सउदी मूल के पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या में मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। ज्ञातव्य है कि अहमद बिन अब्दुल अजीज ने लंदन में अरब प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि अरब में जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है उसके पीछे सउदी अरब के युवराज का हाथ है। बताया जाता है कि सउदी अरब के शाह अपने बेटे को युवराज के पद से हटाने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि अमेरिका द्वारा इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वे युवराज को हटा दें।

एक अन्य समाचार के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईब इर्दोगन के खिलाफ अरब मीडिया में जबर्दस्त अभियान चलाया जा रहा है। सउदी अरब के मीडिया का दावा है कि पत्रकार की हत्या में सउदी युवराज का हाथ नहीं है मगर युवराज को बदनाम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एक अन्य प्रमुख पत्रकार ने तुर्की सरकार पर आरोप लगाया है कि जमाल खशोग्गी की हत्या में उसका भी हाथ है। पत्रकार ने दावा किया है कि तुर्की के गुप्तचर विभाग को इस बात की जानकारी थी कि जमाल खशोग्गी की हत्या करने के लिए सउदी अरब से एक विशेष दल भेजा गया है मगर इसके बावजूद तुर्की ने जमाल खशोग्गी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और ना ही उसे सउदी वाणिज्य दूतावास जाने से रोका। इससे प्रतीत होता है कि यह सब जानबूझकर हुआ है।

सियासत (17 नवम्बर) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार तुर्की सरकार ने पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या के बारे में सउदी अरब के दावे को गलत बताया और कहा कि एक वीडियो में दावा किया गया है कि जमाल खशोग्गी की हत्या सुनियोजित ढंग से हुई थी। तुर्की का कहना है कि इस हत्या में सउदी अरब के युवराज का हाथ था और इसके बारे में कई प्रमाण उपलब्ध हैं। सउदी अरब सरकार ने दावा किया कि जमाल खशोग्गी की हत्या के बारे में सउदी अरब के पांच नागरिकों को मौत की सजा दी जा रही है जबकि युवराज का इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। 59 वर्षीय पत्रकार जमाल खशोग्गी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के विरोधी थे जिनकी 2 अक्टूबर को इस्ताम्बूल स्थित सउदी अरब दूतावास में हत्या कर दी गई थी। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इस हत्या में बड़े लोगों का हाथ था मगर उन्होंने युवराज का नाम नहीं लिया। पत्रकार अब्दुल तकदीर साल्वे ने दावा किया कि जमाल खशोग्गी की हत्या गला घोंटकर की गई थी मगर दूसरे वीडियो में साफ हो जाता है कि जमाल खशोग्गी की हत्या सुनियोजित ढंग से की गई थी और हत्या करने के लिए 15 हत्यारों का जो टोला सउदी अरब से भेजा गया था वह होटल में बैठे हुए जमाल खशोग्गी की हत्या के तरीकों पर विचार-विमर्श कर रहा था। तुर्की के पास इस बात के प्रमाण भी हैं कि हत्यारों ने विदेश में कई फोन किए और इस बात की सूचना दी कि हत्या का मिशन पूरा हो चुका है। जबकि सउदी अरब

सरकार के अनुसार इस हत्याकांड में 11 व्यक्ति लिप्त थे जबकि 21 व्यक्ति इस समय पुलिस हिरासत में हैं जिनमें से पांच को मौत की सजा दी जाएगी जिन्होंने जमाल खशोग्गी की हत्या के निर्देश दिए थे और हत्या की थी।

दावत (16 नवम्बर) के अनुसार सउदी अरब के सरकारी वकील ने घोषणा की है कि पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या में युवराज का कोई हाथ नहीं है। प्रवक्ता को अनुसार जमाल खशोग्गी की हत्या करने से पूर्व उसे बेहोश किया गया था और उसके बाद शव के टुकड़े-टुकड़े किए गए। फिर इन टुकड़ों को दूतावास के बाहर एक एजेंट के हवाले कर दिया गया। इस बात का खंडन किया गया है कि इस बात को लेकर युवराज को कोई जानकारी थी। सउदी अरब के गुप्तचर विभाग के उप-प्रमुख ने जमाल खशोग्गी को सउदी अरब लाने का निर्देश दिया था जबकि इस्ताम्बूल में पहुंचे दल के प्रमुख ने इसकी हत्या करने के निर्देश जारी कर दिए।

इंकलाब (14 नवम्बर) के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या करने के बाद एक हत्यारे ने सउदी अरब में फोन करके उसे बताया था कि अपने बॉस को बता दो कि उसका मिशन पूरा हो गया है। तुर्की गुप्तचर विभग के अनुसार इस कॉल में बॉस का संकेत सउदी अरब के युवराज से है। सूत्रों के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स को प्राप्त सूचना के अनुसार अब्दुल अजीज ने तुर्की से सउदी अरब फोन किया था और एक उच्चाधिकारी को बताया था कि वो बॉस को बता दे कि उसका काम हो गया है। सउदी गुप्तचर विभाग ने दावा किया है कि अमेरिकी समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह सब गलत है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस वीडियो को ना तो देख सकता है और ना ही सुन सकता हूं क्योंकि वीडियो बहुत भयानक है। तुर्की ने यह ऑडियो-वीडियो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और सउदी अरब सहित कई देशों को उपलब्ध करवाया है। सउदी अरब के विदेश मंत्री ने इस बात को पुनः दोहराया है कि इस हत्या में सउदी अरब के युवराज का कोई हाथ नहीं है।

II

गाजा में जंग बंदी

इंकलाब (14 नवम्बर) ने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है, 'हमास की ताकत से इजरायल भयभीत'। समाचार के अनुसार गाजा में फिलीस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के रॉकेटों के हमलों से डरकर इजरायल ने युद्धविराम करने की घोषणा की है। युद्धविराम करने में मिस्र ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ज्ञातव्य है कि गाजा में इजरायल की स्पशेल यूनिट की फौज ने सात फिलीस्तीनियों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में हमास ने इजरायल पर चार सौ रॉकेट चलाए थे। जिनसे पूरे इजरायल में भय फैल गया था। इस रॉकेट हमले में दो यहूदी मारे गए थे और कई जख्मी हुए थे। इसके बाद इजरायल ने गाजा में विमान के हवाई हमले शुरू कर दिए थे जिनमें 6 और फिलीस्तीनी मारे गए थे। इसके बाद हमास ने इजरायल को धमकी दी थी कि वह गाजा पर तुरन्त हमले बंद करे वरना और रॉकेट हमलों के लिए तैयार रहें। हमास के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल ने गाजा पर हमला करने की एक व्यापक योजना बनाई थी मगर फिलीस्तीनियों ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि इजरायल के हमले से कम से कम छह फिलीस्तीनी मारे गए हैं जबकि इजरायल

ने दस नागरिकों के घायल होने के समाचार को स्वीकार किया है। एक इजरायली भी रॉकेट के हमलों में मारा गया है। इजरायल ने टीवी चैनलों की कई इमारतें तबाह कर दी। इसके बाद अल-कसा टीवी चैनल का प्रसारण बंद हो गया। ज्ञातव्य है कि गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लम्बी और 10 किलोमीटर चौड़ी है और इसमें 19 लाख लोग रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता ने दावा किया है कि हम इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इजरायल और फिलीस्तीन दोनों से अनुरोध किया कि वह जंग बंद करें। अगर युद्धविराम नहीं हुआ तो नया विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तुर्की ने इजरायल से हमले बंद करने की अपील की है। अन्त में तुर्की के हस्तक्षेप से इजरायल और फिलीस्तीन के बीच समझौता हो गया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि इजरायल दोहरी चाल चल रहा है। एक ओर तो वह अरब देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की नौटंकी कर रहा है और दूसरी ओर वह फिलीस्तीनियों को अपना निशाना बना रहा है।

III

सउदी अरब में हजारों इंजीनियरों की छुट्टी

सियासत (12 नवम्बर) के अनुसार सउदी अरब सरकार ने विदेशियों को नौकरी से हटाने का जो अभियान छेड़ रखा है उसके तहत अब तक 11,811 विदेशी मूल के इंजीनियरों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उनकी जगह सउदी अरब के नागरिकों की नियुक्ति की गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार चालू वर्ष में हजारों विदेशियों को नौकरी से हटाया जा चुका है और उनकी जगह 1,91,000 सउदी नागरिकों को नौकरी दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि स्थानीय लोगों को नौकरी देने का ये अभियान जारी रखा जाएगा।

IV

अरबों दीनार का घोटाला

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (16 नवम्बर) के अनुसार मुक्तादा अल-सदर ने मांग की है कि सरकारी बैंक में जिन लोगों ने अरबों दीनार का घोटाला किया है उनके खिलाफ जांच शुरू की जाए और सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक के प्रबंधकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि वर्षा के कारण सात अरब दीनार के नोट पानी में बह गए थे। वह सही नहीं हैं क्योंकि बैंक के अंदर रखे हुए अरब दीनार के नोट पानी नहीं बह सकते। यह भ्रष्टाचार का मामला है जिसके बारे में सरकार को तुरन्त जांच करके राष्ट्रीय कोष को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हाल में ही इराक के राष्ट्रीय बैंक के गर्वनर ने दावा किया था कि हाल की वर्षा के दौरान पानी एक बैंक में भर गया था जिसके कारण कम से कम सात अरब दीनार के नोट पानी में बह गए। अमेरिका मुद्रा में ये रकम पचास लाख डॉलर के लगभग होती है।

V

ईरान में सरकार के खिलाफ महागठबंधन

अखबार मशरिक (20 नवम्बर) के अनुसार ईरान की दस विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए एक महागठबंधन बनाने की घोषणा की है। इस महागठबंधन द्वारा जारी किए गए एक वक्तव्य के अनुसार महागठबंधन में शामिल विभिन्न पार्टियों ने स्वीकार किया है कि हालांकि उनमें आपसी वैचारिक मतभेद हैं मगर इसके बावजूद वर्तमान प्रशासन को बदलने के लिए वह एकजुट हुए हैं। इस महागठबंधन द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि वह देश में एक फेडरल लोकतंत्र के ढांचे की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे। इसका मुख्य लक्ष्य राजनीति के धर्म से अलग करना होगा। यह महागठबंधन धार्मिक, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, सभी नागरिकों के समान अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, तमाम ईरानियों को आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस महागठबंधन का कहना है कि हम वर्तमान ईरानी लोकतंत्र के शासन से आशा नहीं करते कि वह कोई वास्तविक सुधार करेगा इसलिए जरूरी है कि वर्तमान इस्लामी व्यवस्था को समाप्त किया जाए और ईरान में लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित किया जाए। इसमें ईरान के विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले और क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं।

VI

जॉर्डन का इजरायल से शांति समझौता समाप्त

इंकलाब (23 अक्टूबर) के अनुसार जॉर्डन ने इजरायल से हुए शांति समझौते को समाप्त करने की घोषणा की है और कहा है कि इजरायल को जॉर्डन के क्षेत्रों में फसलें उगाने से रोक दिया जाएगा। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि हम अब इजरायल के साथ हुए शांति समझौते की अवधि में कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे क्षेत्रों में इजरायल को कृषि उपज करने की अनुमति नहीं होगी। अब हमारे अपने नागरिक ही इसका लाभ उठाएंगे। ज्ञातव्य है कि 1994 में जॉर्डन और इजरायल के बीच हुए समझौते में तय किया गया था जॉर्डन के क्षेत्र 5 हेक्टेयर जमीन को 25 वर्ष की लीज पर इजरायल को दी जाएगी और इस जमीन पर इजरायली नागरिक फसल उगा सकेंगे। जानकार सूत्रों के अनुसार इजरायल का प्रयास है कि शांति समझौते की अवधि को बढ़ाया जाए।

विश्व

I

मुस्लिम महिलाएं अमेरिकी कांग्रेस के लिए निर्वाचित

इत्तेमाद (8 नवम्बर) के अनुसार अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में दो मुस्लिम महिलाएं अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी गई हैं। इनके नाम रशीदा तलीब और इल्हान उमर हैं। रशीदा तलीब फिलीस्तीनी मूल की अमेरिकन नागरिक हैं, जबकि इल्हान उमर सोमालिया की रहने वाली हैं। इन दोनों का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। उन्होंने कहा कि हमने नया इतिहास बनाया है। जब हमें टिकट दिया गया था तो विश्वास नहीं था कि हम चुनाव जीत पाएंगे। इल्हान उमर 12 वर्ष की आयु में सोमालिया से शरणार्थी बनकर अमेरिका आई थी और उसने कई बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा मुसलमानों पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया था। इन दोनों महिलाओं के अतिरिक्त चार हिन्दुस्तानी मूल के लोग भी इन चुनावों में विजयी रहे हैं। इनमें अमी बेरा, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल और राजा कृष्णमूर्ति शामिल हैं।

समाचारपत्र के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुस्लिम महिला को अमेरिका की संसद का कांग्रेसी सदस्य चुना गया हो। रशीदा तलीब की उमर 42 वर्ष है। रशीदा तलीब और इल्हान उमर हिजाब पहनती हैं। इन दोनों की जीत के बाद अमेरिकी संसद में मुस्लिम महिलाओं की संख्या बढ़कर अब तीन हो गई है। समाचारपत्र ने कहा कि अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना तेजी से बढ़ रही है और हाल के वर्ष में मुसलमानों के खिलाफ अपराधों की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समाचारपत्र ने स्वीकार किया है कि इन मुस्लिम महिलाओं को विजयी बनाने में मस्जिदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन क्षेत्रों की मस्जिदों में निरन्तर इमाम इन मुस्लिम महिलाओं को विजयी बनाने के लिए नमाज़ियों से अपील करते रहे हैं और इमामों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इन मुस्लिम मलिाओं को विजयी बनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि वे अमेरिकी संसद में मुसलमानों के हितों की रक्षा कर सकें। मस्जिदों की अपील का उन क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों पर विशेष प्रभाव हुआ और मुसलमानों ने पहली बार अपने मतों का इस्तेमाल किया। समाचार में प्रकाशित एक सम्पादकीय में कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव परिणामों से ट्रम्प को गहरा झटका लगा है। 7 वर्ष के बाद विपक्षी पार्टी को निचले सदन में बहुमत प्राप्त हो गया है। जिसके कारण अब ट्रम्प को मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। इस सदन में ट्रम्प की पार्टी को 51 और विरोधी पार्टी को 43 सीट मिली हैं। अमेरिका में अब अगला राष्ट्रपति चुनाव 2020 में होगा और अगले दो वर्ष ट्रम्प के लिए काफी कठिनाई भरे होंगे। हालांकि अमेरिका का इतिहास रहा है कि मध्यावधि चुनाव में हमेशा विपक्षी दल जीतता रहा है। 1934 से लेकर अब तक 21 बार ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें सिर्फ तीन बार ही सत्तारूढ़ दल को बहुमत प्राप्त हुआ।

II

बांग्लादेश चुनाव में भाग लेंगे विपक्षी दल

सियासत (12 नवम्बर) के अनुसार बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने घोषणा की है कि आगामी माह देश में होने वाले आम चुनाव में वह भाग लेगी। ज्ञातव्य है कि इस पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया

जेल में बंद हैं और उन्हें भ्रष्टाचार के दो मुकदमों में कई वर्ष की सजा हो चुकी है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 2014 में हुए आम चुनाव का बांग्लादेश के सभी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था और इसके बाद अवामी लीग की शेख हसीना सत्ता में आई थीं। संयुक्त मोर्चा और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मांग की है कि चुनाव का कार्यक्रम एक माह के लिए स्थगित किया जाए। ज्ञातव्य है कि चुनाव आयोग ने इससे पूर्व घोषणा की थी कि 23 दिसम्बर को देश में मतदान होगा। मगर मतदान की तिथियों को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में भारी मतभेद पाया जाता है।

III

बलात्कार के आरोप में मुस्लिम विद्वान गिरफ्तार

सियासत (17 नवम्बर) के अनुसार फ्रांस के सबसे प्रमुख इस्लामी विद्वान तारिक रमजान को दो महिलाओं से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 56 वर्षीय तारिक रमजान को जमानत के लिए तीन लाख यूरो की धनराशि निर्धारित की गई है। जमानत पर रिहा होने के लिए उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस में जमा करवाना होगा और प्रत्येक सप्ताह थाने में हाजिरी देनी होगी। तारिक पर दो महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप हैं जिनमें से एक महिला अपंग है और दूसरी महिला मानवाविधकार कार्यकर्ता है। तारिक रमजान ने दावा किया था कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया था मगर बाद में उसे अपना बयान वापस लेना पड़ा। क्योंकि सरकार की ओर से चार सौ के करीब संदेश न्यायालय में पेश किए गए थे। जिनसे इस बात की पुष्टि होती थी कि तारिक रमजान के इन महिलाओं के साथ यौन संबंध थे। बाद में तारिक रमजान ने दावा किया कि यह संबंध आपसी सहमति से बने थे।

IV

पाकिस्तान में पूर्व पुलिस अधिकारी की हत्या

अखबार मशरिक (19 नवम्बर) के अनुसार बलूचिस्तान के प्रमुख नगर क्वेटा में कुछ अज्ञात आक्रमणकारियों ने एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या की जिम्मेवारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। सेवानिवृत्त डीआईजी मोहम्मद नईम को उस वक्त गोली का निशाना बनाया गया जब वह मस्जिद से नमाज अदा करके घर जा रहे थे। उन पर मोटरसाइकिल सवार कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई जिससे घायल होकर वह गिर गए और बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिस हथियार से इस पूर्व पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया गया है उसका इस्तेमाल इससे पूर्व भी कई पुलिस अधिकारियों की हत्या में किया जा चुका है। जिस पूर्व पुलिस अधिकारी की हत्या की गई उसका पुत्र नगर के थाने का प्रमुख है। तालिबान ने एक प्रेस-विज्ञप्ति में कहा है कि क्योंकि इस पूर्व पुलिस अधिकारी ने तालिबान के कई नेताओं की हत्या की थी इसलिए उसे निशाना बनाया गया है।

V

सात लाख अफगानियों की वापसी

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (16 नवम्बर) के अनुसार सरकारी सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान और ईरान में रहने वाले अफगान शरणार्थियों में से सात लाख से अधिक लोग वापस आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थी एजेंसी के अनुसार इस वर्ष जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक 7,56,000 अफगान नागरिक पाकिस्तान और ईरान से स्वदेश लौट चुके हैं। इनमें से अधिकांश शरणार्थी वे हैं जो कि अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ने के बाद ईरान पलायन कर गए थे। ईरान से वापस आने वालों की संख्या 6,71,000 है। जबकि पाकिस्तान से लौटने वाले अफगानियों की संख्या सिर्फ 29,000 है।

इंकलाब (18 नवम्बर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है और 35 लाख लोग भुखमरी का शिकार हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों से मांग की है कि भुखमरी का शिकर होने वाले इन लोगों के लिए खाद्य की व्यवस्था की जाए। प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान के 40 सूबों में से 35 सूबों में बारिश ना होने के कारण पानी की बहुत कमी है। भूख से तंग आकर दो लाख अफगान नागरिक अपने घरों से पलायन कर गए हैं। चारा ना होने के कारण भेड़-बकरियां काफी संख्या में मर रही हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार इन अफगानों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए आठ करोड़ अस्सी लाख डॉलर की आवश्यकता है।

VI

ऑस्ट्रेलिया को इस्लाम से खतरा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (15 नवम्बर) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उनके देश को सबसे बड़ा खतरा हिंसावादी और अतिवादी इस्लाम से है। ज्ञातव्य है कि मेलबर्न में सोमालिया मूल के एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला किया था, जिस पर सुरक्षा सैनिकों ने उसे गोली से उड़ा दिया था। पुलिस के अनुसार जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उसका संबंध अतिवादी इस्लामी संगठन आईएसआईएस से था और उसके हमले में एक व्यक्ति मारा गया था व दो लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री ने मुसलमानों से आग्रह किया है कि वे मुस्लिम सम्प्रदाय में इस बात की अपील करें कि अतिवादी इस्लामी विचारधारा उनके देश में न फैले।

VII

तब्लीगी जमात के प्रमुख का निधन

इंकलाब (19 नवम्बर) के अनुसार पाकिस्तान में तब्लीगी जमात के अमीर हाजी मोहम्मद अब्दुल वहाब का निधन हो गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार उनका निधन डेंगू के कारण हुआ है। हाजी दिल्ली में पैदा हुए थे और उन्होंने इस्लामिया कॉलेज

लाहौर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। पाकिस्तानी तब्लीगी जमात के वे तीसरे अमीर थे। उन्हें विश्व के मुस्लिम विद्वानों की सूची में भी शामिल किया गया था।

VIII

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कार्यक्रम में धमाका

इंकलाब (22 नवम्बर) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौलवियों के एक कार्यक्रम में धमाका होने से कम से कम पचास इमाम मारे गए और सौ से अधिक घायल हो गए। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह धमाका ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर एक हॉल में इमामों के सम्मेलन में हुआ। जानकार सूत्रों के अनुसार एक आत्मघाती आक्रमणकारी बारूदी जैकेट पहनकर सम्मेलन में शामिल हुआ और उसने धमाके के साथ अपने आपको उड़ा लिया। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या और भी अधिक है। जिहादियों ने जानबूझकर इमामों और धार्मिक नेताओं को अपना निशाना बनाया है। इस वर्ष का यह सबसे बड़ा हमला बताया जाता है। अभी तक इसकी जिम्मेवारी किसी संगठन ने नहीं ली है।

अन्य

I

अबू आसिम आजमी के खिलाफ मुकदमा

अखबार मशरिक (15 नवम्बर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लखनऊ के एक थाने में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आजमी ने राज्य के मुख्यमंत्री का उल्लेख करते हुए कहा था कि आजमगढ़ आजम शाह का बसाया हुआ नगर है, योगी के बाप का बसाया हुआ शहर नहीं है। इसी तरह से उन्होंने नरेन्द्र मोदी के बारे में कहा था कि 2019 में भाजपा की हार होगी और मोदी इसके बाद गुजरात वापस जाएंगे। धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का रहेगा। उनके इस बयान पर भाजपा के निजामाबाद के उपाध्यक्ष हनुमन्त प्रसाद की शिकायत पर सराय मीर थाना में आजमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद नगर में विवाद शुरू हो गया है।

II

वीडियो कॉल पर निकाह

अखबार मशरिक (15 नवम्बर) के अनुसार मोबाइल पर वीडियो कॉल द्वारा निकाह करना जायज है या नहीं इस मुद्दे पर मुसलमानों के धार्मिक विद्वानों में भारी मतभेद हैं। मगर इसके बावजूद जब सउदी अरब में नौकरी करने वाले एक युवक को छुट्टी न मिल सकी तो वीडियो कॉल द्वारा निकाह करवाने का निर्णय किया गया। मामला जिला गोंडा के कर्नलगंज गांव का है। यहां का रहने वाला रमज़ान सउदी अरब में नौकरी करता है। रमज़ान का निकाह गोंडा के राधाकुंड गांव की रहने वाली अकबरी के साथ तय हुआ था। रमज़ान ने अपने निकाह का हवाला देकर छुट्टी मांगी थी मगर उसके मालिक ने उसे छुट्टी नहीं दी। छुट्टी न मिलने के कारण परिजन परेशान हो गए। आखिरकार तय किया गया कि निकाह वीडियो कॉल द्वारा किया जाए। निर्धारित समय पर बारात गोंडा के एक मैरिज हॉल में पहुंची। दुल्हे को वीडियो कॉल किया गया और काज़ी ने वीडियो कॉल पर ही निकाह पढ़ा दिया। इसके बाद दुल्हे के परिजन दुल्हन को लेकर अपने घर चले गए।

III

इमामों के वेतन वृद्धि की मांग

अखबार मशरिक (18 नवम्बर) ने एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली और हरियाणा की मस्जिदों के इमामों व मोज़ानों ने वेतन वृद्धि को लेकर यूनियनबाजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने पहले समाचारपत्रों में बयानबाजी से की थी। इसके बाद जुलूसों का सहारा लिया। समाचारपत्र ने आंदोलन का रास्ता अपनाने की

आलोचना की है। लेख में दावा किया गया है कि इमाम वक्फ बोर्ड को ब्लैकमेल करके अपना वेतन, चिकित्सा भत्ता, हाउस रेंट और बच्चों की फीस वक्फ बोर्ड से देने की मांग कर रहे हैं। लेखक ने शिकायत की है कि वक्फ बोर्ड के नियमों के अनुसार जो मतवली या प्रबंध समितियां स्थापित की गई हैं वह मस्जिदों की दुकानों को किराए पर देते समय पगड़ी के नाम पर भारी धनराशि वसूल करते हैं मगर वह मस्जिदों के इमामों और मोज़ानों को इतना कम वेतन देते हैं कि उन्हें मोहल्लों में रहने वाले लोगों से रोटियां मांगनी पड़ती हैं। लेख में मांग की गई है कि वक्फ बोर्ड ने हरियाणा और दिल्ली में इमामों का वेतन बढ़ाने की घोषणा तो कर दी है मगर उसे लागू नहीं किया। समाचारपत्र ने कहा है कि दोनों राज्यों की सरकार ने इमामों के वेतन में वृद्धि करने का जो आश्वासन दिया है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि इमामों को यूनियनबाजी और आंदोलन का रास्ता अपनाना न पड़े।

IV

जिहादियों का शिकार पुलिस अधिकारी

इंकलाब (18 नवम्बर) के अनुसार कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा एक दारोगा की हत्या करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अंसार उल हक नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस जिहादी का संबंध आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन से है। उसने एक महिला की सहायता से इम्तियाज मीर नामक पुलिस अधिकारी को गोली से उड़ाया था। अंसार उल हक ने पुलिस को बताया कि उसने इस पुलिस अधिकारी की हत्या आतंकी संगठन के प्रमुख के निर्देश पर की थी और इसमें उसकी एक प्रेमिका शाहिदा भी शामिल थी। बताया जाता है कि इस महिला ने अधिकारी को उसके कार्यालय से बाहर बुलाया था। इसके बाद इस महिला ने अधिकारी को कहा कि उसे वह उसके घर छोड़ आए और इस बारे में युवती ने आतंकवादियों को सूचना दे दी। इस पर अंसार उल हक और उसके एक साथी ने इस दरोगा की हत्या कर दी। बताया जाता है कि हत्या के बाद दिल्ली आया ओर फिर बेंगलुरु से मुम्बई गया था और वहां से दिल्ली आ रहा था। पकड़ा गया व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त है और सेब का कारोबार करता है। काफी समय से वह एक जिहादी संगठन के सम्पर्क में था। उसकी प्रेमिका भी उच्च शिक्षा प्राप्त थी। बताया जाता है कि पूछताछ के दौरान इस व्यक्ति ने हत्यारों के नाम भी पुलिस को बताए हैं।

V

आसिया अंद्राबी के खिलाफ मुकदमा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (15 नवम्बर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली के एक न्यायालय में कश्मीरी आतंकी महिला आसिया अंद्राबी और उसके दो साथियों के खिलाफ पटियाला हाउस के एक न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया है। आरोप-पत्र राष्ट्रीय जांच एजेंसी के न्यायालय में आसिया अंद्राबी और उसकी सहयोगी फहमिदा और नाहिद के खिलाफ दायर किया गया है। इन तीनों के खिलाफ देशद्रोही गतिविधियों को भड़काने और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का आरोप है। ये तीनों जुलाई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आरोप-पत्र के अनुसार तीनों ट्वीटर, फेसबुक और यू-ट्यूब द्वारा, जिनमें पाकिस्तान

के चैनल भी शामिल हैं, भारत के खिलाफ विद्रोह और घृणा फैलाने वाली सामग्री का प्रसारण करती थी और वो जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करके हिंसा द्वारा उसे पाकिस्तान में शामिल करने की समर्थक हैं। इस आरोप-पत्र के अनुसार आसिया अंद्राबी का पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद से गहरा संगठन है।

VI

जर्मनी में जिहादी संगठन पर छापे

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (15 नवम्बर) के अनुसार जर्मनी पुलिस ने इस्लामी तंजीम नामक एक संगठन के 15 कार्यालयों पर छापे मारकर काफी मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और अन्य सामग्री जब्त की है। सरकार का आरोप है कि इस संगठन का संबंध आतंकी गतिविधियों से है और उसे विदेशों से सहायता मिलती है। यह संगठन अतिवादी संगठन सल्फी से जुड़ा हुआ है। अभी तक जर्मनी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

Latest Publications

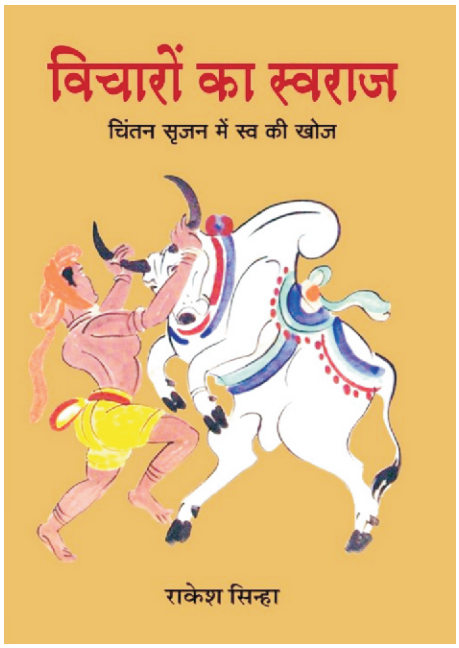

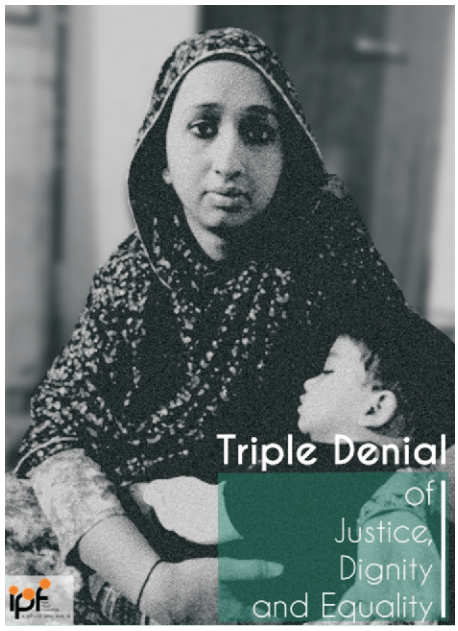

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org